

many others had been dismissed in the Birla-owned paper for holding views which were contrary to theirs. I welcome his statement that the independence of the press is not complete until the editorial freedom is conceded. Therefore, I wanted to know as to why Government has not taken prompt measures wherever such complaints came. After all, under the Industrial Disputes Act, a worker can go to a tribunal and get justice. But the editorial department people cannot get justice. There is serious lacuna in the present law. I want to know whether the Minister or the Government is thinking of taking steps in this direction to protect the freedom of the press and right of freedom of expression of an individual.

SHRI I. K. GUJRAL : The hon. Member of the House has clarified a few things. I am in agreement with him. I think the Working Journalists Act was primarily incorporated for that very purpose. Unfortunately, at that stage, some editors had felt that they should not be brought within the purview of the Working Journalists Act. I hope they will have second thoughts about it.

SHRI T. N. SINGH: In the absence of that, why don't you take some intermediate step?

SHRI I. K. GUJRAL: I am willing to sit with you.

SHRI T. N. SINGH: It was done in the case of Verghese.

SHRI I. K. GUJRAL: I am willing to sit with anybody, not for individual cases— that may not be wise—but I think we should think in terms of institutional safeguards.

SHRI T. N. SINGH: It is of topical interest.

SHRI I. K. GUJRAL: I think whatever be the line of action, it is better that we discuss it in a small group. But institutional safeguard for editorial freedom is a necessity and a must.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के स्वरूप पर मुद्रा-स्फीति का प्रभाव

*470. सरदार कुमार सं. चं. आंग्रे :

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

श्री सुब्रमण्यम् स्वामी :

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मूल स्वरूप पर मुद्रा स्फीति का कितना प्रभाव पड़ा है; और

(ख) उसके परिणाम स्वरूप योजना के लक्ष्यों को कितनी क्षति पहुँची है और योजना की शेष अवधि में इन लक्ष्यों में और क्या परिवर्तन किए जाने का विचार है ?

■ Effect of inflation on layouts of the Fifth Plan.

*470. SHRI S. C. ANGRE :

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR :

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY :

SHRI O. P. TYAGI :

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) to what extent inflation has affected the original layouts of the fifth Five Year Plan; and

(b) to what extent objectives of the plan have received a setback as a result thereof and what further changes in the objectives are contemplated during the remaining period of the Plan?]

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri O. P. Tyagi [] English translation.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Exercises to determine the impact of inflation on the original outlays of the Draft Fifth Plan are under way and it may be premature to discuss them at this stage.

(b) The Draft Fifth Plan is being reviewed in the light of all the relevant factors and every effort is being made to maintain the basic objectives as far as possible through necessary additional efforts and adjustments in plan allocations and priorities.

[योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप के मूल परिवर्तनों पर मूला-स्फीति के प्रभाव का निश्चय करने के लिए अभ्यास किए जा रहे हैं और इस समय उन पर विचार-विमर्श करना असामयिक होगा।

(ख) सभी सम्बन्धित घटकों को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना के प्रारूप की समीक्षा की जा रही है और योजना आवंटनों और प्राथमिकताओं में आवश्यक अतिरिक्त प्रयत्न कर जहाँ तक सम्भव होगा कुनियादी उद्देश्यों को बनाये रखने का प्रयत्न किया जायेगा।]

श्री आम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, पंचवर्षीय योजना की कई वर्षों की घोषणाओं के पश्चात् आज मंत्री महोदय इस स्थिति में हैं कि पंचवर्षीय योजना अभी गर्भ में है अभी विचार उन पर चल रहा है। मैं यह समझ पा रहा हूँ कि वह गर्भ में नहीं है उसका गर्भपात हो चुका है; अर्थात् हो चुका है पंच वर्षीय योजना का। मैं यह जानना चाहूँगा कि जब आपने पंच वर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई उसके पश्चात् से मूला स्फीति इतनी बढ़ गई है कि रूपरेखा का मूल्य आज 25 पैसे रह गया है। और योजनाओं के लिए आपने जितना धन निश्चित किया था उस धन का चौथाई मूल्य रह गया है। इसके अलावा आपने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो अनुमान किया था वह लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में मैं यह जानना चाहता

हूँ कि आपकी पंचवर्षीय योजना किस आधार पर चल रही है? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहूँगा कि जब आपने पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनाया था और उसका स्वरूप निर्धारित किया था तो उस वक्त रूपरेखा का क्या मूल्य था और क्या यह भी सत्य है कि अब रूपरेखा का मूल्य सिर्फ 25 पैसे रह गया है? ऐसी हालत में योजना का पूरा आउटलेट क्या है और वर्तमान स्थिति में रूपरेखा का मूल्य जिस प्रकार से गिर गया है उसका देखते हुये अब पंचवर्षीय योजना का आउटलेट क्या हो सकता है और क्या यह भी सत्य है कि पंचवर्षीय योजना लगभग समाप्त हो गई है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सभापति जी, माननीय सदस्य चाहें या न चाहें, पंचवर्षीय योजना चल रही है, समाप्त नहीं हुई है और यह गर्भ में भी नहीं है। इस बात को सब जानते हैं कि इस वक्त जो वित्तीय वर्ष है, यह पांचवीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष है। हम पिछले 20 नवम्बर से 1975-76 के वर्ष में किस प्रकार से इस वार्षिक योजना में हमारी जो प्राथमिकताएँ थीं उनको कार्यान्वित करने के लिए उनके ऊपर सम्पूर्ण रूप से वर्तमान स्थिति का ध्यान में रखते हुए गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। यह विचार विभिन्न मंत्रालयों के साथ, विभिन्न राज्य सरकारों के साथ हो रहा है। इसलिए माननीय सदस्य की यह भावना कि पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई है या समाप्त हो जाये, मुझे दुःख है कि पूरी नहीं हो रही है। जहाँ तक मूला-स्फीति का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जरूर बढ़ी है। मुझे यह बात कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि जब हमने पंचवर्षीय योजना निरूपित की थी तो उस समय जो स्थिति थी उस स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इसीलिए मैंने अपने उत्तर में कहा कि उस परिवर्तन का ध्यान में रखते हुये हमें बहुत-सी चीजों को फिर से ध्यान देना पड़े रहा है। यह बात इसलिए नहीं हो रही है कि जो हमारी मान्यताएँ थी उनमें कोई फर्क आया है या जो हमारे उद्देश्य थे उनमें

कोई फर्क आया है या जो हमारी नीति थी उसमें कोई फर्क आया है। यह इसलिए किया जा रहा है कि हमारे पास जितने साधन थे उन साधनों में बहुत कमी आई है और मुद्रा-स्फीति के कारण और पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो चांगुनी वृद्धि हुई है उन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों पर विचार हो रहा है और हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे देश की उन्नति और हमारे देश के विकास की जो रफ्तार थी उस रफ्तार में किसी प्रकार की कमी न आने पाये। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि पंचवर्षीय योजना किसी प्रकार से समाप्त नहीं हुई है। यह तेजी से चलेगी और चलाई जाएगी। जहाँ तक आउटलेट का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो मुद्रा-स्फीति बढ़ी है और हमारे पास जो साधन हैं उनका किस प्रकार से और कितना उपयोग किया जा सकता है, इस पर हमने साँच-विचार किया है और कुछ विचार, जैसा मैंने कहा, चल रहा है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय मेरा स्पीसिफिक क्वेश्चन था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुद्रा-स्फीति का ध्यान में रखते हुए आपने पंचवर्षीय योजना का कितना आउटलेट रखा है ? वर्तमान स्थिति में हमारे देश में जो मुद्रा का प्रसार हुआ है और रुपये का मूल्य 25 पैसे रह गया है उसका ध्यान में रखते हुए आपने पंचवर्षीय योजना का आउटलेट क्या रखा है ? क्या आप कुछ योजनाओं को समाप्त कर रहे हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मेरी मुश्किल यह है कि माननीय सदस्य ने मेरे द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान से नहीं सुना है। मैंने यह कहा है कि वर्तमान स्थिति में हमारे देश में जो मुद्रा-प्रसार हुआ है और जिस प्रकार से हमारे साधनों में अन्तर आया है उसको ध्यान में रखते हुए हम इस बात को निर्धारित कर रहे हैं कि किस प्रकार से अपने उद्देश्यों या हमारे जो प्लान्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो टारगेट्स हैं, उनको पूरा किया जाय।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : एक तरफ तो मंत्री महोदय कह रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस पर हम साँच-विचार कर रहे हैं। इन दोनों बातों में विरोधाभास है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यदि आपने मेरी बातों का ध्यान से सुना होता तो आपने सारी स्थिति का समझ लिया होता। मैंने यह कहा है कि योजना के इस एक साल में बहुत-सी चीजों में भारी परिवर्तन आया है। वह परिवर्तन अभी भी चल रहे हैं, यह बात नहीं कि वे परिवर्तन रुक गए हैं पूरी तरह से। इसलिए जब हम 1975-76 की योजना पर विचार कर रहे हैं, अभी तक जो परिवर्तन हुए हैं उन पर विचार करें, जो उसकी प्रायोरिटीज हैं, जो उसके एलोकेशंस हैं उनका फिर से री-अरेंज कर रहे हैं और इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं है। जो हमने पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बना कर सदन के सामने प्रस्तुत किया था उस जमाने से आज बहुत अंतर आ गया है, माननीय सदस्य की इस बात को मैं मंजूर नहीं करता हूँ। इसलिए फिर से उस बारे में तय करना है कि कितना पैसा हमारे पास उस मुद्रा-स्फीति का था और अब है और उसके बीच जो कमी है उसको किस ढंग से पूरा करें और किस ढंग से पैसा लगाएं और भागत के विकास के लिए लगाएं और वह साँच-विचार चल रहा है। इस बीच मैंने हमें आवश्यक योजना के लिए जो विचार विमर्श करना है वह हम कर रहे हैं और आज की जो वर्तुस्थिति है उसका ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। इसलिए हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Please put a specific supplementary now without discussion.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं स्पीसिफिक ही पूछूंगा। लेकिन मैं आपका प्रॉटेक्शन भी चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि क्या शुरू में योजनाएं बनीं और आपके पास रिसोर्सिज कम हो गए तो क्या योजनाओं के स्वरूप में कोई कमी आने की संभावना इस प्रकार की है ? मैंने यह पूछा था कुछ प्रोजेक्ट्स कम करेंगे या नहीं करेंगे ? इस प्रकार की बात पूछी थी लेकिन जवाब नहीं दिया गया।

अब मरे दूसरे सप्लीमेंट्री का थोड़ा सा जवाब दे दीजिए। अध्यक्ष महादय, केवल रूपए के मूल्य में ही नहीं, बल्कि अभी आपने कहा, तेल के मूल्य में वृद्धि हुई है, विदेशी सहायता जिस समय आपने पंचवर्षीय योजना बनाई उस समय आपको विदेशी सहायता ज्यादा मिलने की आशा थी पर अमरीका आदि बहुत से देशों ने अपनी सहायता को कम किया। दूसरा फ़ैक्टर जो देश में वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि लगातार हो रही है, एनफ्लेशन अधिक है, उस मूल्य-वृद्धि का कारण एक फ़ैक्टर यह है, तो इसका प्रभाव आपकी पंचवर्षीय योजना के आउटले पर क्या पड़ने का अनुमान है? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिस समय आपने पंचवर्षीय योजना बनाई उस समय आपका जो डीफिशिट था उसका अनुमान कितना था और आपके प्रयत्न करने के बाद, टैक्स आदि लगाने के पश्चात्, डीफिशिट कितना होने की संभावना है जिसका प्रभाव इस फिफ्थ फाइव प्लान पर पड़ेगा? पंचवर्षीय योजना में उसके आधार पर आपका अनुमानित आउटले कितना होगा?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महादय, मैंने कहा कि अनुमानित आउटले जो हमारा है उसमें हमने किसी प्रकार का अंतर किया नहीं पर उस अनुमानित आउटले में जितना हम काम कर सकते थे, मुद्रा-स्फीति के कारण उतना काम हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुद्रा-स्फीति के बढ़ जाने के कारण अब हर चीज की कीमतें बढ़ गईं। यह बात मैंने पहले भी कही थी और माननीय सदस्य बार-बार चेहरा रहे हैं। जो हमारे मुख्य उद्देश्य हैं योजना के उन मुख्य उद्देश्यों में किसी प्रकार का अंतर न आए इसलिए, जिसको हम कोर सेक्टर कहते हैं अंगरेजी में, उस पर हम नए तरह से सांच विचार कर रहे हैं आज जो स्थिति हमारे देश में है उसको लेकर हम जिसका अपना मूल उद्देश्य मानते हैं, जिनके आधार पर हम भारत की प्रगति करना चाहते हैं . . .

श्री आनंदप्रकाश त्यागी : विचार नहीं, योजना बताइए, उसमें क्या कोई परिवर्तन हो रहा है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं बता रहा हूँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जहाँ तक मूल

उद्देश्य हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। मैं आपसे साफ़ बात इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत भारी अंतर हमारी आर्थिक स्थिति में आया है और इसलिए इस चीज का बहुत गंभीरता से विचार करके और विचार विमर्श करके ही तय करना पड़ेगा। पर जो हमारी नीति है वह यह है कि जो मूल उद्देश्य और मूल तथ्य हैं, उसमें हम किसी प्रकार की फेरबदल न करें जिससे जो हमने आर्थिक उन्नति करनी है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो। जहाँ तक अपने डीफिशिट फाइनेंसिंग के बारे में पूछा है मैं आपको बताऊँ कि हमने यह तय किया है कि डीफिशिट फाइनेंसिंग हमारे देश में 125 करोड़ रु. से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका अख्तियार में रखा जाय और इस काम को करने के लिए जो कदम उठाये गये हैं, उनके बारे में माननीय सदस्य का अच्छी तरह से मालूम है और मैं उन चीजों को दोहरा कर सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता हूँ। हमारा यह उद्देश्य है कि 125 करोड़ रुपये से ज्यादा डीफिशिट फाइनेंसिंग न हो पाये किसी भी प्रकार से।

श्री आनंदप्रकाश त्यागी : मैंने अनुमानित पूछा है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने कहा कि इस बारे में सांच विचार होगा।

SHRI V. B. RAJU: The hon. Minister is pleased to say that the basic approaches of the Fifth Plan, are not altered, and there is no intention of altering them. And it is a good thing. But a new situation has developed that there is a wide gap between the exports and the imports, and an adverse balance of payment position is taking place in a big way. In the context of this, I would say that while the Plan was being Formulated certain resources have been taken to the credit side which are not available now. Will the Minister be pleased to say whether still the principle of net zero aid stands? Will it stand still or is the Government inclined to have a rethinking in the context of the adverse balance of payment position?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I said that at present exercises are going on in the Planning Commission and in the Planning Ministry to determine the financial strategy to achieve the basic and core objectives and therefore I would not be able to give any specific answer to the hon. Member's question which is a very important question about the net zero aid and things like that. Therefore, I would say that unless these matters are decided and finalised by us, it would be premature on my side to state anything. About deficit financing, may I say that deficit financing of Rs. 125 crores was with reference to the present, that is, the current, financial year of 1974-75. For the Fifth Plan period, deficit finance has been taken at Rs. 1,000 crores.

SHRI N. G. GORAV : I do not know why the Minister was so dogmatic in maintaining that the Plan structure remains as it is and that our objectives also remain as they are. I would like to draw your attention to the fact that the Finance Minister, Shri Subramaniam, himself has said in a public meeting that the entire Fifth Plan will have to be recast. Now, I would like to know from him as to what will be the direction in which the Fifth Plan will be recast because it really indicates that it does not remain what it was before. If you remember, some of the Members of Parliament were associated with the deliberations. Financial aid was given to the Fifth Plan, but all of a sudden, because of so many other changes, the Plan had to be abandoned. Now, I would like to know from him whether the recommendations of the Fuel Policy Committee will be taken into consideration, whether it is a fact that Mr. Shenoy has pointed out that during the last 20 years we have imported grains worth four thousand or five thousand crores and therefore the best policy would be not to import any food but to create it here, to see to it that the agrarian community gets the maximum incentives and whether that will be taken into consideration. What will be the lines? I do not want him to give a complete answer, but I would like him to indicate what are the

lines along which the Fifth Plan will be recast.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Even though the hon. Member may not like a full answer, I would like to give it. The structural changes in the Plan are in the offing. That I have myself stated. But the objectives, the fundamental strategy and the approach and the policy framework are not going to change.

SHRI N. G. GORAV: Removal of poverty is one of the fundamental objectives. Of course, it will not be changed.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Naturally, it will not be changed. Therefore what I am saying is while we are considering all these matters, the resources position and other things, the fundamental approach—I would like to indicate—is that as far as possible within our resources, we do not wish to change the allocations or priorities of such categories of subjects which come in the core sector of the Plan. And, therefore, we have taken into consideration the Shenoy Committee's report. We have also taken into consideration the food imports etc., which the hon'ble Mem-as drawn our attention to and many other things and we are seriously engrossed in these studies and consultations, and I hope we will be able to complete this soon enough so that we can give final shape to the Fifth Five Year Plan.

Structural changes are bound to take place because of the fundamental changes that have taken place in the inflationary conditions in the country and in the world. Also the conditions in the country have undergone qualitative changes. Therefore, while the fundamental objectives, the strategy, the basic policy framework, remains intact, we are only changing the structure so that we can achieve our core sector aims and do not disturb the envisaged growth factor or growth rate that we have indicated in the Draft Fifth Plan.

SHRI KRISHAN KANT: May I know from the hon'ble Minister whether, since

Mr. Subramaniam's document for bringing self-reliance was made, and the objective to that effect was launched upon, it is not a fact that we have borrowed more money from abroad in the last two years than during the last several Plans? If so what are the reasons therefor?

Secondly, Sir, according to Government records in 1964-65, 40 per cent, of the Indian population was below poverty line but now according to the economists more than two-thirds of the Indian population are below the poverty line. If it is so, may I know what is the strategy of the Government to see that this poverty line does not reach 95 per cent, and goes down to 70 per cent? May I know what steps the Government are taking in this direction?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Sir, it may be true that more borrowing may have been done in recent past than was originally envisaged. I do not dispute this point. The hon'ble Member and the House know the compelling reasons how these crept into our planning structure. As far as the poverty line is concerned there are different viewpoints of different economists in their own fields. As far as the National Sample Survey reports are concerned, up to last year they indicate that people living below the poverty line are about 40 per cent., and not as much as the hon'ble Member has suggested. But I am not saying that this is the last word in this matter. There can be difference of opinion in this particular thing. For taking out more population of this country from this section of poor people we are making these exercises in the Plan not only to stop this process but also to remove the poverty as much as possible. The whole strategy is outlined in the Draft Five Year Plan.

श्री रवी राय : अध्यक्ष महोदय, वावजूद इसके कि मंत्री महोदय कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है यह अभी भी बरकरार है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही नहीं है कि चौथी पंचवर्षीय योजना

के खत्म होने के बाद भी, जैसा कि उन्होंने खुद माना है लोक सभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कि 22 करोड़ लोग दरिद्रता की सीमा रेखा के नीचे हैं और करीब दस, पंद्रह करोड़ लोग बेकार हैं और 38 करोड़ 80 लाख लोग अनपढ़ हैं और आप की पंचवर्षीय योजनाओं का यह नतीजा है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन के जो प्रीडिसेसर मोहन धारिया जी थे उनकी अध्यक्षता में साधारण जनता का एसोशियल कमीडिटीज देने के सिलसिले में एक धारिया कमेटी बँठी थी, उसकी मुख्य-मुख्य रिपोर्ट-इंशन्स क्या थीं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की कि साधारण जनता का एसोशियल कमीडिटीज पहुँच सकें और पब्लिक डीस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या सिफारिशों धारिया कमेटी ने की थीं और सरकार ने उसपर क्या कार्यवाही की ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही, वह उनकी राय हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो समाजवाद पर विश्वास करते हैं तो उनको मालूम होगा कि यदि हम योजना को यहाँ लागू नहीं करते और अपना विकास योजनाबद्ध ढंग से करने का प्रयत्न न करते तो जो भी हमारे देश की आज हालत है वह उससे ज्यादा बदतर होती।

श्री रवी राय : प्लान्ड इकानामी और प्राइस बढ़ना एक साथ चलता है क्या . . . ?

श्री राजनारायण : श्रीमन्, क्या मंत्री जी ऐसा उत्तर देंगे जिसका कोई अर्थ है ? यदि रवी राय समाजवाद में विश्वास करते हैं तो उनकी योजना का समर्थन हो। क्या यह उत्तर है ? समाजवाद क्या है ?

(Interruptions)

श्री रवी राय : वह पाइंट आफ आर्डर पर है। आप बँठ जाइए। बार-बार खड़े हो जाते हैं . . . ।

(Interruption)

श्री राजनारायण : आप मंत्री जी को यह कहें कि मंत्री जी समाजवाद का मखौल न करें।

समाजवाद में सत्ता का विकेंद्रिकरण होता है, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में . . .

(Interruption)

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्रीमान, यह बात बिलकुल साफ है कि यदि हम योजनाबद्ध विकास अपने देश का नहीं करते तो जितनी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उससे कहीं ज्यादा कठिनाइयाँ आज होतीं। इसलिए आज जो हमारे यहां परेशानियाँ हैं, जो कठिनाइयाँ हमें अनुभव करनी पड़ रही हैं, वह योजना के कारण नहीं हैं। योजना यदि नहीं होती तो और योजनाबद्ध विकास नहीं होता तो इससे ज्यादा कठिनाइयाँ हमको अनुभव करनी पड़तीं।

दूसरी बात इन्होंने धारिया कमिटी के बारे में कही। धारिया कमिटी की रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं वह राज्य सभा के सभापटल पर रख दी गई हैं और सदस्यों को जो उनकी सिफारिशें हैं वह मालूम हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो समिति की सिफारिशें हैं वह सरकार के विचाराधीन हैं।

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, Members of Parliament were divided into five groups for consultation over the draft Fifth Five-Year Plan.

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

I belonged to one of those. There opinions were given and recommendations were made. May I know what is happening to the recommendations of Committees A, B, C and D which made certain vital recommendations for formulation of the Plan? Do I understand that they have been completely ignored? I should like to know from the Government how many years they will take even to produce a presentable draft Fifth Five-Year Plan? Sir, we had a Plan document, then 'Approach to the Plan' and then an 'Outline'. I should like to know when and how the draft Fifth Plan will come.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Let him answer.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: It is ! hon. Member knows that the recommendations made by the Parliamentary Committees that were set up have been considered in the Parliament Consultative Committee attached to the Ministry of Planning. We attach the highest importance to the opinions expressed by the hon. Members and they are all being taken into consideration while we are considering the present fiscal situation, the present financial situation, to re-structure the Fifth Five-Year Plan. About the time, may I tell the hon. Member that we have not taken undue time. The situation has been changing so fast that unless we take the actualities into account and unless we go on firm assumptions, again we will be in a difficult situation if we go on, assuming something which is likely to change in the next two or three months' time. Therefore, we are constantly at it and I can assure the hon. Member that there would be no let-up from our side and there would be no delay from our side. We are very anxious to give a final shape to the Fifth Five-year Plan as quickly as possible so that the entire thing is definite for us to take action upon.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kadershah.

श्री राजनारायण : यह तो स्पष्ट करें कि ये अनफॉरसीन क्या हैं ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have called Mr. Kadershah.

SHRI M. KADERSHAH: What is the quantum of money, out of Rs. 1,400 crores assessed by the Wanchoo Committee as black money, that has since been seized by the Government to combat inflation so as to put the Plan in a correct perspective? I would like to know whether the Government proposes to shift their priorities for Plan implementation from the core sector to any other item and, if so, what is that. And how far is it likely to achieve a balanced development ? I would also like to suggest in this connection that the Planning Minister should consult the State Governments on allocation of priorities for

development in the respective areas. I would also like to know whether the Central Government will encourage formation of State Planning Boards for fuller exploitation of the resources.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You should conclude now. Let the Minister reply.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I could not follow the first part of his question. As far as core sector is concerned, our attention is focussed on that and we want to see that the main objectives of the core sector are achieved. As far as State Governments are concerned, we are consulting them. Without consultation we will not take any final decision in these matters. State Planning Boards have been formed in certain States. In certain States they are doing very useful work and I hope they will have their own structure «o that they can help the Central Planning Commission.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

f[Indo-Swiss collaboration for manufacture of watches..

घड़ियों के निर्माण के संबंध में भारत तथा स्विटजरलैंड के बीच सहयोग

*471. श्री राजनारायण : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री 21 नवम्बर, 1974 का राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 220 के दिए गए उत्तर का दोहोरा और बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्विटजरलैंड की एक फर्म भारत में घड़ियों के निर्माण के संबंध में किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

*471. SHRI RAJNARAIN : Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to the reply to

Starred Question 220 given in the Rajya Sabha on 21st November, 1974 and state:

(a) whether a firm from Switzerland is contemplating a scheme for manufacturing watches in India,

(b) if so, the details thereof?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. पी. मौर्या) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

*j-[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise]

Damodar Valley Corporation

*472. SHRI L. MAHAPATRO : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Damodar Valley Corporation has undertaken an ambitious expansion programme to overcome power crisis in the eastern region; and

(b) if so, what are the broad outlines thereof?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

ia) and (b) The total installed capacity in Damodar Valley Corporation at present is 1181 MW. During the Fifth Five-Year Plan, it is proposed to increase this generating capacity by an addition of 680 MW, which would be adequate to meet the growth of load demands within the Valley.